

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 28/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा

दायरा दिनांक: 8.2.2018

अन्तर्गत धारा: 76 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

- 1 आनन्दीबाई पुत्री सुक्खा जाति भोई निवासनी खातोली पत्नी किशनगोपाल जाति भोई निवासिनी हाल नैनवा तहसील नैनवा जिला बूंदी।

बनाम

- 1 ग्राम पंचायत खातोली जरिये सरपंच
- 2 पुरुषोत्तम पुत्र मांग्या जाति भोई निवासी खातोली
- 3 ग्यारस्या पुत्र सुक्खा जाति भोई निवासी खातोली
- 4 अशोक कुमार पुत्र श्यामलाल जाति कलाल निवासी खातोली
- 5 ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी ब्राहमण पाडा श्योपुर जिला श्योपुर म०प्र०।
- 6 ओमप्रकाश पुत्र घनश्याम जाति खाती निवासी बेडावदा तहसील श्योपुर म०प्र०।
- 7 सुरेश शर्मा पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
- 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा।



...अपीलार्थी

...रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रमाकांत लोहिया अभिभाषक रेस्पोंड कम-1
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अभिभाषक रेस्पोंड कम-2 व 3

::निर्णयः

दिनांक 5.12.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 143/2015 बउनवान आनन्दीबाई बनाम ग्राम पंचायत खातोली वगैरा अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 11.1.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि सेटलमेंट से पूर्व ग्राम खातोली मे अपीलांट के पिता सुक्खा वल्द नेनगा भोई निवासी खातोली के दर्ज आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा , ख० नं० 296 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, ख० नं० 473 रकबा 9 बिस्वा कुल 3 किता रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा का सुक्खा की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत खातोली द्वारा तस्दीक नामा० सं० 93 दिनांक 7.7.1958 बिना वारिसान के सजरे की जांच किये भाई मांग्या व ग्यारस्या के पक्ष मे तस्दीक कर दिया गया जबकि अपीलांट भी मृतक की जायदां पुत्री थी। अतः इन्तकाल विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जावे। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर निर्णय दिनांक 11.1.2018 से खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून न्याय एवं तथ्यों के विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील बेरून मियाद मानकर खारिज करने मे त्रुटि की है जबकि अपीलांट ने नामान्तरकरण की की सर्वप्रथम जानकारी का सही विवरण देकर अपील प्रस्तुत की है। विवादित आराजी पैतृक है जो सुक्खा जी के खाते थी तथा जब सुक्खा जी का स्वर्गवास हुआ तब अपीलांट की आयु 10 वर्ष की थी जिसको जमीन व राजस्व रिकार्ड की

नित. सं. बाबू
कोटा

जानकारी नहीं थी। उक्त विवादित आराजी में अपीलांट का 1/3 हिस्सा निहित है जिसको वह अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारणी है ऐसी स्थिति में विधि विरुद्ध तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलांट शादी के बाद पति के साथ नैनवा में निवास करती है तथा वह अपने भाईयो पर पूरा भरोसा करती थी इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड देखने की कोई जरूरत नहीं आई। नामान्तरकरण में ना तो सजरा दर्ज किया गया ना ही परिवार के सदस्यों का नाम अंकित किया गया। सुक्खा की मृत्यु के बाद भाई मांग्या व ग्यारस्या के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। उक्त कार्यवाही गुपचुप तरीके से हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण नहीं कर जेरअपील आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास 1958 में हो गया था। गलत नामा० तस्दीक हो जाने से उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर रेस्प० क्रम 2 के पिता मांग्या का स्वर्गवास हो गया। रेस्प० क्रम 2 ने इन्द्राज का फायदा उठाकर उक्त आराजी के नये ख० नं० की आराजी ख० नं० 411 रकबा 0.83 है० दक्षिण दिशा की रेस्प० क्रम 4 ता 7 को विक्रय करदी है तथा मांग्या के अन्य वारिस मुन्नी, भंवरी एवं मांग्या की पत्नी रामप्यारी ने जरिये हक त्याग उनके हिस्से की आराजी रेस्प० क्रम 2 पुरुषोत्तम के ह कमे रिलीज डीड द्वारा छोड़ दी उक्त हिस्सा आराजी में भी अपीलांट का हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के बीच लम्बित प्रकरणों की जो छाया प्रतियां पेश की गई है उससे उक्त अपील के मेरिट पर निस्तारण करने में कोई फर्क नहीं पडता है। अवैधानिक आदेश को चुनौती देने/निरस्त करने की कोई सीमा नहीं है पक्षकार को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर उसको चलेन्ज किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जेरअपील 11.1.2018 निरस्त किया जावे तथा नामान्तरकरण सं० 93 निरस्त किया जाकर उपरोक्त आराजी में अपीलांट का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्प० क्रम 4, 5, 6, 7 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर तामील पूर्ण मानी गई तदुपरांत अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलांट एवं रेस्प० क्रम-1 लगायत 3 सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नामा० सं० 93 बिना वारिसान की जांच किये तस्दीक किया गया है। विवादित आराजी खातेदार स्व० सुक्खा के मांग्या, ग्यारस्या पुत्र एवं अपीलांट पुत्री है अतः स्व० सुक्खा की आराजी में अपीलांट का 1/3 हक हिस्सा निहित है। ग्राम पंचायत द्वारा मृतक सुक्खा का फौती नामान्तरकरण सं० 93 तस्दीक किया गया जिसमें अपीलांट का नाम छोड़ दिया गया। नामा० कौरम द्वारा तस्दीक नहीं किया गया। सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 8 अनुसार अपीलांट मृतक खातेदार की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस उत्तराधिकारी है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पुत्री आनन्दीबाई को नोटिस नहीं दिया ना ही उत्तराधिकार की जांच की गई। विवादित आराजी के नामा० की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय में नामा० के विरुद्ध अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय गुणावगुण पर विचार किये बिना ही मियाद के बिन्दू पर आलौच्य निर्णय पारित कर खारिज करने में त्रुटि की है क्योंकि जहां प्रकरण में कानूनी व सारवान तथ्य निहित हो तो मियाद के बिन्दू को गौण माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 45, आरबीजे 1998 पेज 43 आरबीजे 1997 पेज 178 आरआरडी 1998 पेज 319, डीएनजे(सुप्रीम) 2017 पेज 928, आरआरडी 1982 पेज 332, डीएनजे(सुप्रीम) 2015 पेज 592, आरआरडी 1996 पेज 457 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपीलांट की अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय 11.1.2018 एव नामा० सं० 93 अपास्त किया जावे।।
- 4 विद्वान अभिभाषक रेस्प० क्रम 1 व 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि नामा० 93 दिनांक 7.7.1958 को तस्दीक किया गया है जो काफी पुराना है। अपीलांट द्वारा वर्ष 1958 में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.10.95 को अपील पेश कर चुनौती दी गई है जो अवधि बाधित होने से अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गुणावगुण पर विचार किये बिना मियाद के बिन्दू पर खारिज की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलौच्य जेरअपील निर्णय विधिसम्मत है। विद्वान अभिभाषक रेस्प० क्रम 1 व 2 ने आलौच्य निर्णय के अंतिम पैरा में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकट किये गये अभिमत की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये कथन किया कि अपीलांट को राजस्व रिकार्ड की सम्पूर्ण जानकारी होने के बावजूद न्यायालय के सम्मत् उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 7.10.15 को होना वर्णित किया गया जबकि वस्तुतः राजस्व

रिकार्ड की जानकारी अपीलालाटा को लम्बे से समय होने के बावजूद भी अपील के साथ संलग्न शपथ पत्र में असत्य कथन अंकित किये जाकर अपील पेश की गई थी। बहस में आगे कथन किया निर्णय प्रार्थना पत्र सं० 97/97 दिनांक 1.2.1997 एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राज० अजमेर की पत्रावली की आदेशिका एवं निर्णय दिनांक 25.2.2000 तथा वाद न्याया० एसडीओ इटावा बउनवान मांगीबाई बनाम मांगीलाल में अपीलालाटा पक्षकार होने से उसको उक्त नामा० की जानकारी पहले से होने की पुष्टि करते हैं। अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2016 पेज 226, आरबीजे 2000 (7)पेज 358 आरबीजे (24) 2017 पेज 95 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन कर प्रकरण में उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर गौर किया गया। अपीलालाटा द्वारा नामा० सं० 93 दिनांक 7.7.1958 ग्राम खातौली खातेदार सुक्खा के फौत होने उपरांत उसके सुलभी लडके मॉग्या, ग्यारस्या के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत खातौली द्वारा तस्दीक किया गया है। अपीलालाटा ने उक्त नामा० को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में दिनांक 19.10.2015 को प्रथम अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत प्रस्तुत कर अपील में मृतक सुक्खा की पुत्री होना वर्णित करते हुये विवादित आराजी में स्वयं का 1/3 हिस्सा निहित होने एवं नामान्तरकरण में उसका नाम छोड़ दिये जाने से नामा० सं० 93 को खारिज करने हेतु प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलालाटा द्वारा प्रस्तुत अपील में मियाद सम्बन्धी असत्य अंकित किये जाने से अपील को मियाद के बिन्दू पर निर्णय दिनांक 11.1.2018 से खारिज किया है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलालाटा का मुख्य तर्क है कि "नामान्तरकरण सं० 93 कोरम द्वारा तस्दीक नहीं कर सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया जिसमें अपीलालाटा का नाम छोड़ दिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलालाटा मृतक खातेदार की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है। सरपंच द्वारा आनन्दीबाई को नोटिस नहीं दिया ना ही उत्तराधिकार की जांच की गई। अधीनस्थ न्यायालय अपील का मेरिट पर निर्णय नहीं कर मियाद के बिन्दू पर खारिज कर त्रुटि की है क्योंकि जहां प्रकरण में कानूनी व सारवान तथ्य निहित हो तो मियाद के बिन्दू को गौण माना गया है"। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेष्पो० क्रम 1 व 2 ने नामा० सं० 93 की जानकारी अपीलालाटा को पूर्व से ही होना तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील में तथा शपथ पत्र में जानकारी के संबध में गलत तथ्य अंकित किये जाने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को जेरअपील निर्णय 11.1.2008 से मियाद के बिन्दू पर खारिज किया है जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल दस्तावेजात प्रार्थना पत्र सं० 97/97 दिनांक 1.2.1997 एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राज० अजमेर की पत्रावली की आदेशिका एवं निर्णय दिनांक 25.2.2000 तथा न्याया० एसडीओ इटावा में जेरकार वाद बउनवान मांगीबाई बनाम मांगीलाल में अपीलालाटा पक्षकार होने से उसको नामा० सं० 93 की जानकारी पहले से होने की पुष्टि करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील तथा संलग्न शपथ में असत्य तथ्य अंकित किया जाना प्रकट होता है। उक्त तथ्यों के आलोक में विद्वान अभिभाषक अपीलालाटा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक नजीरें आरआरडी 1984 पेज 45, आरबीजे 1998 पेज 43 आरबीजे 1997 पेज 178 आरआरडी 1998 पेज 319, डीएनजे(सुप्रीम) 2017 पेज 928, आरआरडी 1982 पेज 332, डीएनजे(सुप्रीम) 2015 पेज 592, आरआरडी 1996 पेज 457 चस्या नहीं होती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रकरण में तथ्यों का समुचित विवेचन करते हुये अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइश प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलालाटा सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 5.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति० सहायक न्यायाधीश
कोटा